RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 23 से 29 अगस्त 2025 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 12 | अंक-55 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

मध्यप्रदेश अब बनेगा क्रिटिकल मिनरल्स हब: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मध्यप्रदेश में मिला रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार, चीन पर निर्भरता होगी समाप्त

भोपाल: मध्यप्रदेश के सिंगरौली में रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE) की खोज भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि मध्यप्रदेश अब क्रिटिकल मिनरल्स हब बनेगा, जो ऊर्जा राजधानी के साथ-साथ खनिज राजधानी के रूप में भी जाना जाएगा। यह खोज भारत को ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाएगी, जिससे चीन जैसे देशों पर निर्भरता खत्म होगी।

सिंगरौली: क्रिटिकल मिनरल्स का भविष्य

कोल इंडिया लिमिटेड के शोध में सिंगरौली की कोयला खदानों और चट्टानों में REEs (स्कैंडियम, यिट्रियम आदि) की सांद्रता 250-400 पीपीएम पाई गई। जुलाई 2025 में इसकी आधिकारिक घोषणा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि कोयले की राख और ओवरबर्डन भी भविष्य में क्रिटिकल मिनरल्स का स्रोत बन सकते हैं। यह खोज भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देगी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी।

IREL के साथ सहयोग

राज्य सरकार REEs के प्रसंस्करण और शोध के लिए बुनियादी ढांचा विकसित कर रही है। खनिज संसाधन विभाग ने इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (IREL) की भोपाल इकाई के साथ सहयोग पर चर्चा की है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की योजना है, जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और उद्योग को विश्वस्तरीय आधार प्रदान करेगा।

REEs के उपयोग

रेयर अर्थ एलिमेंट्स आधुनिक उद्योगों का आधार हैं:

- रक्षा और अंतरिक्ष: सैमरियम-कोबाल्ट, नियोडिमियम चुम्बक हथियारों और उपग्रहों में।
- पेट्रोलियम: लैंथेनम, सेरियम उत्सर्जन कम करने में।
- इलेक्ट्रिक वाहन/पवन ऊर्जा: स्थायी चुम्बक।
- डिस्प्ले/प्रकाश: यूरोपियम, यिट्रियम (एलईडी, एलसीडी)।
- स्वास्थ्य: गैडोलीनियम (MRI), ल्यूटेटियम (कैंसर उपचार)।

वैश्विक नेतृत्व की ओर

सिंगरौली की यह खोज भारत को ग्रीन एनर्जी और उच्च-तकनीकी उद्योगों में आत्मनिर्भर बनाएगी। मध्यप्रदेश न केवल ऊर्जा बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स की राजधानी बनेगा, जिससे भारत वैश्विक मंच पर शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा।

भारत में सभी iPhone 17 मॉडल्स के निर्माण की तैयारी में एप्पल

भोपाल: तकनीकी दिग्गज एप्पल पहली बार भारत में अपने सभी iPhone 17 मॉडल्स का निर्माण करने की योजना बना रहा है, जिसमें प्रीमियम प्रो वेरिएंट्स भी शामिल हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने भारत में पांच कारखानों में उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसमें हाल ही में शुरू हुए दो नए संयंत्र शामिल हैं। यह कदम अमेरिका के लिए निर्यात किए जाने वाले iPhone मॉडल्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करने और व्यापारिक शुल्क के जोखिमों से बचने की रणनीति का हिस्सा है।

अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच भारत से iPhone निर्यात $7.5 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के पूरे $17 बिलियन का लगभग आधा है। यह दर्शाता है कि भारत तेजी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तमिलनाडु में टाटा ग्रुप का होसुर संयंत्र और बेंगलुरु हवाई अड्डे के पास फॉक्सकॉन का उत्पादन केंद्र इस विस्तार के केंद्र में हैं। टाटा के संयंत्र अगले दो वर्षों में भारत के iPhone उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा संभाल सकते हैं, जो इसे एप्पल के प्रमुख साझेदार के रूप में स्थापित करता है।

यह बदलाव अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और कोविड-19 महामारी के बाद आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण हुआ है। एप्पल को वर्तमान तिमाही में $1.1 बिलियन के शुल्क प्रभाव की उम्मीद है, जिससे भारत पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी हो गया है। हालाँकि, ट्रम्प प्रशासन ने iPhone जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को क्षेत्रीय शुल्कों से छूट दी है, लेकिन देश-विशिष्ट शुल्क का जोखिम बना हुआ है।

इस कदम से भारत का वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थान मजबूत होगा, जिसमें नौकरियों के अवसर और तकनीकी हस्तांतरण में वृद्धि होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देगा, लेकिन गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बनाए रखने की

चुनौतियाँ रहेंगी। सितंबर में होने वाले लॉन्च के साथ, भारत से बने iPhone 17 मॉडल्स अमेरिकी बाजार में पहली बार उपलब्ध होंगे, जो इस बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है।

Source: News 18

संसद ने खान और खनिज संशोधन विधेयक पारित किया

भोपाल: संसद ने खान और खनिज (विकास और नियमन) संशोधन विधेयक, 2025 को मंगलवार को पारित कर दिया, जो भारत के खनन क्षेत्र में बड़े सुधारों का मार्ग प्रशस्त करता है। यह विधेयक, जो मूल रूप से 1957 के खान और खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम में संशोधन करता है, को 12 अगस्त को लोकसभा और 19 अगस्त को राज्यसभा में ध्वनिमत से मंजूरी मिली। इस विधेयक का उद्देश्य खनन क्षेत्र को आधुनिक, गतिशील और आत्मनिर्भर बनाना है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों पर ध्यान केंद्रित करना।

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं। विधेयक के तहत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) का नाम बदलकर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट किया गया है, और इसके दायरे को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्वेषण और विकास के लिए विस्तारित किया गया है। इसके लिए पट्टाधारकों से शुल्क 2% से बढ़ाकर 3% किया गया है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में खनिज पट्टों में रणनीतिक खनिजों जैसे लिथियम, ग्रेफाइट, निकल और कोबाल्ट को बिना अतिरिक्त शुल्क के जोड़ने की अनुमति शामिल है। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जो वर्तमान में आयात पर निर्भर है। इसके अलावा, कैप्टिव खानों से खनिजों की बिक्री पर 50% की सीमा हटाई गई है, जिससे खनिजों का अधिकतम उपयोग संभव होगा। खनन पट्टों में संचित खनिज डंपों की बिक्री की भी अनुमति दी गई है, जो पर्यावरणीय जोखिम को कम करेगी और राज्यों को अतिरिक्त राजस्व प्रदान करेगी।

हालांकि, विपक्ष ने राज्य सरकारों के अधिकारों और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंता जताई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक भारत को वैश्विक खनिज बाजार में मजबूत स्थिति दिला सकता है, बशर्ते पारदर्शिता और स्थायित्व सुनिश्चित हो। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण है।

Source: ETV Bharat

GST Cut Cools Down AC Prices, Fuels Market Growth

Bhopal: In a move set to cool down costs for consumers, the Indian government has announced a reduction in the Goods and Services Tax (GST) on air conditioners, lowering the rate from 28% to 18%. This decision, effective from October 2025, is expected to reduce AC prices by up to Rs 2,500, making cooling solutions more affordable for households and businesses alike.

The GST cut comes as a relief for both consumers and manufacturers. Air conditioners, long considered a luxury item taxed at the highest slab, will now be more accessible to middle-class families, particularly in tier-2 and tier-3 cities where demand has been rising. Industry experts predict a surge in sales, with estimates suggesting a 15-20% growth in the AC market over the next year. Companies like Voltas, Daikin, and LG are gearing up to capitalize on this opportunity by ramping up production and introducing budget-friendly models.

The price reduction is a direct result of the lower tax burden. For instance, a 1.5-ton split AC, previously priced at around Rs 40,000, could see its cost drop to approximately Rs 37,500. This affordability is expected to drive demand, especially in regions experiencing hotter summers due to climate change. Additionally, the reduction aligns with the government's push for energy-efficient appliances, as manufacturers are likely to pass on savings to consumers while promoting eco-friendly models.

The move has been welcomed by industry bodies like the Consumer Electronics and Appliances Manufacturers Association (CEAMA). This is a game-changer for the sector, said CEAMA

President Jasbir Singh. "Lower prices will boost penetration in rural and semi-urban markets, while manufacturers can scale operations, creating jobs and economic growth."

However, some analysts caution that the price drop may vary depending on supply chain costs and raw material prices, which have been volatile. Despite this, the overall sentiment remains positive, with retailers anticipating a festive season boom. As temperatures rise and disposable incomes grow, the GST reduction is poised to make air conditioners a household staple, cooling homes and heating up the market.

Source: Mint

Vision Invest Tech Private Limited | (+91)7389912025
ARN-10613 | visionadvisorymkt@gmail.com
POWERED BY wealthy

Vision Invest Tech Private Limited | (+91)7389912025
ARN-10613 | visionadvisorymkt@gmail.com
POWERED BY wealthy

GST 2.0: Catalyst for a Consumption-Driven Economy

India's Goods and Services Tax (GST) regime is poised for a significant overhaul with the proposed GST 2.0 reforms, announced by Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day speech. Expected to be finalized by Diwali 2025, these reforms aim to simplify the tax structure by consolidating the existing four slabs (5%, 12%, 18%, and 28%) into two primary rates: 5% and 18%, with a special 40% levy on sin goods like tobacco and online gaming. This restructuring is projected to reduce retail prices, boost household savings, and stimulate consumption, with far-reaching implications for various sectors and stock markets. Let's analyse who stands to benefit, which sector stocks may advance, and which could face challenges.

Who Will Benefit?

The GST 2.0 reforms are designed to ease the tax burden on consumers and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). By shifting 99% of goods currently taxed at 12% to the 5% slab and 90% of goods in the 28% slab to 18%, the government anticipates a 4-5% reduction in retail prices for many products. This will enhance affordability for households, particularly for daily-use items, consumer durables, and essential services. MSMEs, burdened by complex compliance, will benefit from procedural simplifications, fostering wider compliance and formalization of the economy. Lower input costs for raw materials, especially for consumer staples, will also improve profit margins for businesses in these sectors.

Sectors Poised to Advance

Several sectors are expected to see significant stock market gains due to increased demand and improved affordability:

1. Automobiles: The reduction of GST from 28% to 18% on vehicles, particularly two-wheelers, small cars, and commercial vehicles, is likely to boost demand by 15-20%, according to Nomura Security Limited estimates. Stocks like Maruti Suzuki, Hero MotoCorp, Ashok Leyland,Bajaj Auto, TVS Motor, and Eicher Motors are key beneficiaries, with Maruti Suzuki already surging 8.9% on reform optimism.

2. Consumer Durables: Products like air conditioners, refrigerators, and televisions, currently taxed at 28%, will become more affordable at 18%. Companies such as Voltas, Havells, Blue Star, Amber Enterprises, and Whirlpool are expected to see demand surges, with analysts projecting a consumption boost during the festive season starting mid-September 2025.

3. FMCG and Retail: Fast-moving consumer goods (FMCG) firms like Hindustan Unilever, Britannia, Nestle, Dabur, and Varun Beverages will benefit from lower raw material costs and increased rural demand, driven by a shift of goods from 12% to 5% tax slabs. Retail and apparel companies such as Trent, Page Industries, and Relaxo Footwear are also likely to gain from improved affordability of garments and footwear priced above ₹1,000.

4. Cement: A GST reduction from 28% to 18% on cement could lower construction costs, benefiting companies like Ultratech Cement. This may improve margins for real estate developers, indirectly boosting housing demand.

5. Financials and Insurance: Banks and non-banking financial companies (NBFCs) like HDFC Bank, ICICI Bank, and Bajaj Finance are expected to see increased credit demand due to higher consumption and lower EMI obligations for consumer durables. Additionally, a potential GST cut on health and life insurance premiums from 18% to 5% or zero could benefit insurers like Niva Bupa and HDFC Life.

Sectors That May Decline

While many sectors will benefit, some may face challenges:

1. Electric Vehicles (EVs): Currently taxed at 5%, EVs may lose their price advantage if internal combustion engine (ICE) vehicles see a GST reduction to 18%. This could impact demand for EV manufacturers like Tata Motors' EV division, as the price gap with ICE vehicles narrows.

2. Oil and Gas: Petroleum products are likely to remain outside the GST ambit, missing out on the benefits of rate rationalization. Stocks like Indian Oil Corporation may see limited upside.

3. IT Services: The IT sector, already facing bearish sentiment with a 0.53% decline in market capitalization, is unlikely to benefit directly from GST reforms, potentially leading to underperformance.

Economic and Market Implications

The reforms are projected to result in a revenue loss of ₹1.5 lakh crore, split equally between the Centre and states, but the government aims to offset this through buoyant tax collections and asset sales. Emkay Global estimates a 50-60 basis point reduction in CPI inflation, potentially prompting RBI rate cuts, which could further boost consumption-driven sectors. However, near-term disruptions may occur as consumers delay big-ticket purchases until the new rates are implemented, and dealers may face inventory losses.

In conclusion, GST 2.0 is set to reshape India's consumption landscape, with automobiles, consumer durables, FMCG, cement, and financials leading the charge. Investors should focus on stocks like Maruti Suzuki, Voltas, Hindustan Unilever, and Ultratech Cement, while exercising caution with EV and IT stocks. As the GST Council finalizes these changes in early Q3 FY26, the market's consumption-over-capex theme will likely gain further traction, offering opportunities for strategic investments.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

Emami Agrotech Enters Branded Staples Market with New Offerings

Bhopal: Emami Agrotech, a key player in the Rs 20,000-crore Emami Group, has made a bold move into the branded staples market, launching its Emami Healthy & Tasty range of atta, maida, and sooji. This strategic expansion targets India's lucrative Rs 80,000-crore branded staples sector, with the company aiming to scale its food vertical to Rs 2,000 crore within the next three to five years.

The launch marks a significant shift for Emami Agrotech, traditionally known for its dominance in edible oils and bio-diesel. Building on its established Healthy & Tasty brand, which already includes spices and soya chunks, the company is now positioning itself as a comprehensive kitchen solutions provider. The move taps into a growing consumer preference for branded staples, driven by demands for hygiene, quality packaging, and brand trust over unbranded alternatives.

Vibhash V Agarwal, Director of Emami Group, emphasized the company's intent to become a central part of Indian households. "More than a category entry, this is a purposeful move to integrate into daily rituals, family meals, and emotional bonds around food," he said. The company plans to leverage its robust distribution network and digitally enabled supply chain to ensure widespread availability.

The initiative begins with a focus on West Bengal, with plans to expand rapidly into markets like Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan, Punjab, and Haryana, where the brand already enjoys strong recognition. Industry analysts view this as a timely step, given the rising demand for branded staples amid changing consumer habits and increasing disposable incomes.

Emami Agrotech's incursion is supported by its decade-long presence in the food sector, starting with edible oils in 2010. The company is also exploring further diversification, with potential launches of ready-to-eat items, snacks, and sausages within the next six months, in collaboration with consultants like McKinsey and Thinking Forks. This expansion could pave the way for an IPO in the next two to three years, signaling ambitious growth plans.

As the market evolves, Emami Agrotech's entry into branded staples is poised to reshape the competitive landscape, offering consumers more choices while strengthening the company's foothold in India's food industry.

Source: Economic Times

Reliance Infrastructure Secures Major NHPC Deal for Solar and Battery Storage

Bhopal: Reliance Infrastructure Ltd has clinched a significant contract from state-owned NHPC, bagging a 390 MW solar power project coupled with a 780 MWhr Battery Energy Storage System (BESS). This landmark deal, awarded at a competitive tariff of Rs 3.13 per kWh, underscores the company's growing dominance in India's renewable energy sector.

Once commissioned, the project will add 700 MWp of solar DC capacity and 780 MWhr of BESS capacity to Reliance Group's portfolio, reinforcing its leadership in clean energy solutions. The initiative is part of a broader 1,200 MW solar and 600 MW/2,400 MWh BESS tender by NHPC, which saw intense competition with 15 bidders, 14 qualifying for the e-reverse auction. The tenders near fourfold oversubscription highlights the surging demand for dispatchable renewable energy.

Reliance Power, a group entity, already boasts a 2.5 GWp solar and 2.5 GWhr BESS capacity, and this addition pushes the group's total clean energy pipeline beyond 3 GWp solar and 3.5 GWhr BESS, cementing its position as India's largest integrated solar-plus-storage player. The project aligns with the nation's push for sustainable energy, leveraging advanced

storage to ensure reliable power supply.Industry experts view this as a strategic move, with the low tariff setting a benchmark for future renewable projects. Reliance Infrastructure's expertise in infrastructure and energy solutions positions it to drive India's transition to a greener future.

Source: The Hindu

नटको फार्मा ने अमेरिका में 180 दिन की विशेषाधिकार के साथ जेनेरिक दवा लॉन्च की

भोपाल: नटको फार्मा लिमिटेड ने बुधवार को घोषणा की कि उसने अमेरिका में बोसेन्टन टैबलेट्स (जो ट्रैक्लियर का जेनेरिक संस्करण है) का लॉन्च किया है, जिसमें 180 दिन की विशेषाधिकार अवधि शामिल है। यह दवा फुफ्फुसीय धमनी उच्च रक्तचाप (PAH) के इलाज के लिए बच्चों में उपयोग के लिए अनुमोदित है। नटको का मार्केटिंग पार्टनर लुपिन लिमिटेड इस उत्पाद को अमेरिकी बाजार में बेचेगा।

नटको ने यूएसएफडीए से अपने संक्षिप्त नई दवा आवेदन (एंडा) के लिए मंजूरी प्राप्त की है और इस उत्पाद के लिए प्रथम-फाइल स्थिति रखता है, जो उसे 180 दिन की विशेषाधिकार अवधि प्रदान करती है। यह दवा 3 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों में पीएएच के इलाज के लिए संकेतित है, जो फुफ्फुसीय संवहनी प्रतिरोध को बेहतर बनाकर व्यायाम क्षमता में सुधार ला सकती है। उद्योग के बिक्री डेटा के अनुसार, पिछले 12 महीनों में बोसेन्टन टैबलेट्स की अनुमानित बिक्री 10 मिलियन डॉलर रही है।

यह लॉन्च नटको की अमेरिकी बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है, जहां कंपनी जटिल और उच्च-मूल्य वाली दवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शेयर बाजार में नटको के शेयर बुधवार को मामूली गिरावट के साथ 888.55 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कंपनी के राजस्व में वृद्धि ला सकता है, हालांकि प्रतिस्पर्धा और नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह पहल भारत की फार्मा

कंपनियों की वैश्विक पहुंच को दर्शाती है।
Source: Economics Times

भारत ने वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन मांग का 10% हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखा

भोपाल: भारत ने 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन मांग का लगभग 10% हिस्सा हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा और शक्ति राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने मंगलवार को फिक्की ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 में यह घोषणा की। वैश्विक मांग के 100 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है, और भारत इस क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, सरकार ने 19 कंपनियों को सालाना 8.62 लाख टन उत्पादन क्षमता आवंटित की है, जबकि 15 कंपनियों को 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण क्षमता दी गई है। नाइक ने कहा, "हम भारत को न केवल बड़े उत्पादक के रूप में, बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।" जून 2025 तक, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 237 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें सौर, पवन और जल विद्युत शामिल हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है।

इस पहल से लगभग 50 मिलियन टन वार्षिक कार्बन उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा स्वतंत्रता में वृद्धि की उम्मीद है। यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय सहयोग भी मजबूत हो रहा है, जिसमें एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक बाजार में अग्रणी बना सकता है, बशर्ते लागत और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर ध्यान दिया जाए।

Source: Business Standard

Manali Petrochemicals Boosts Propylene Glycol Output for Make in India

Bhopal: Manali Petrochemicals Limited (MPL) has expanded its Propylene Glycol (PG) plant, reinforcing its commitment to the 'Make in India' initiative. The state-of-the-art facility, inaugurated recently, will increase production capacity by 50,000 kilotonnes per annum (KTPA), raising the total output to 72,000 KTPA from the existing 22,000 KTPA. Operations will commence once the Tamil Nadu State Pollution Control Board grants the 'Consent to Operate' (CTO), expected soon.

This expansion aligns with the government's push for self-reliance, aiming to reduce India's dependence on imported PG, which currently meets over 75% of the domestic demand of approximately 100,000 tonnes annually. Chairman Ashwin Muthiah hailed the move as a step toward sustainable growth, meeting rising domestic and industrial needs while enhancing India's global manufacturing stature. PG, widely used in pharmaceuticals, food, and industrial applications, will now be more accessible locally, cutting import costs and bolstering economic resilience.

The project, backed by advanced technology and local expertise, reflects MPL's strategy to support the 'Atmanirbhar Bharat' vision. The company plans to leverage this capacity to cater to sectors like food and beverage, where demand is growing at 5-7% yearly. Environmental clearance was secured in 2022, with an initial investment of Rs 150 crore, funded through internal resources, underscoring MPL's financial prudence.

Industry experts view this as a significant stride toward reducing import reliance, though they caution that regulatory delays could impact timelines. MPL's move positions it as a leader in India's petrochemical sector, potentially inspiring similar initiatives. As the facility nears operation, it promises to create jobs and strengthen India's manufacturing ecosystem, aligning with national goals of innovation and self-sufficiency.

Source: Economic Times

ओएनजीसी के अनुसंधान विभाग ने इंजीनियर्स इंडिया के साथ हेलियम रिकवरी डेमो प्लांट के लिए समझौता किया

भोपाल: तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के अनुसंधान एवं विकास विभाग, ओएनजीसी एनर्जी सेंटर ट्रस्ट (ओईसीटी) ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के साथ तमिलनाडु में हेलियम रिकवरी डेमो प्लांट स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 18 अगस्त 2025 को औपचारिक रूप से संपन्न हुआ, जिसकी अनुमानित लागत 39.42 करोड़ रुपये (प्लस जीएसटी) है। यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह प्लांट ओएनजीसी के कावेरी एसेट में कुथलम गैस कलेक्शन स्टेशन पर स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र प्रति घंटे 750 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस को संसाधित करेगा और डिजाइन क्षमता के 110% तक संचालित करने की लचीलापन रखेगा। सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (सीएसआईआर-आईआईपी) द्वारा विकसित तकनीक का उपयोग करते हुए, यह प्लांट प्राकृतिक गैस से 99.995% शुद्धता वाले ग्रेड-ए हेलियम की रिकवरी करेगा। परियोजना की समय-सीमा 18 महीने निर्धारित की गई है, जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), बेसिक इंजीनियरिंग डिजाइन पैकेज (बीईडीपी), डिजाइन, खरीद, निर्माण, कमीशनिंग और प्रदर्शन परीक्षण शामिल हैं।

हेलियम, जो अंतरिक्ष अन्वेषण, अर्धचालक निर्माण, क्रायोजेनिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स और चिकित्सा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संसाधन है, वर्तमान में भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। इस स्वदेशी क्षमता के विकास से देश की तकनीकी प्रगति और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ओएनजीसी के चेयरमैन ए.एस. साहनी ने कहा, "यह परियोजना ओएनजीसी के 'एनर्जी नाउ एंड नेक्स्ट' विजन को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो उन्नत अनुसंधान को व्यावहारिक औद्योगिक अनुप्रयोगों के साथ जोड़ती है।"

ईआईएल और ओईसीटी की विशेषज्ञता का संयोजन इस पहले-प्रकार के प्रोजेक्ट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह पहल 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में योगदान देगी, साथ ही भारत को हेलियम उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में मजबूत स्थिति दिला सकता है, विशेषकर उच्च मूल्य वाले गैसों के क्षेत्र में।

Source: Business Standard

Hindustan Zinc Plans Uranium Venture with Government Approval

Bhopal: Hindustan Zinc, India's leading refined zinc producer, is set to enter uranium mining if the government permits private sector involvement, according to CEO Arun Misra. Speaking to Reuters, Misra emphasized the company's readiness to bid for uranium blocks, aligning with the government's plans to end its decades-old monopoly on the nuclear sector. This move aims to attract significant investment and support Prime Minister Narendra Modi's vision to expand nuclear power capacity twelvefold by 2047.

The decision follows recent indications from government sources that private firms may soon be allowed to mine, import, and process uranium, addressing the nation's growing energy needs. Misra stated, "We will get into atomic minerals, especially uranium, because the country needs it." This strategic shift reflects India's push for energy security amid global supply chain challenges.

Beyond uranium, Hindustan Zinc is diversifying into rare earth minerals, having secured its first block in Uttar Pradesh earlier this year. The company plans to extract neodymium, vital for magnets in motors and generators, within five to six years. It also seeks international partnerships to explore lithium, antimony, and graphite, countering supply disruptions from China's recent export restrictions.

Simultaneously, the company aims to double its zinc production to 2 million

metric tons by 2029. This expansion into critical minerals positions Hindustan Zinc as a key player in India's energy transition, pending regulatory approval and successful collaboration with global firms.

Source: The Hindu

JSW Steel and POSCO Forge Alliance for 6MTPA Steel Plant

Bhopal: JSW Steel, India's premier steelmaker, has partnered with South Korea's POSCO Group to establish a 6 million tonnes per annum (MTPA) integrated steel plant in India. The collaboration, formalized through a non-binding Heads of Agreement (HoA) signed on August 18 in Mumbai, marks a significant step toward bolstering India's steel production capacity. The proposed 50:50 joint venture builds on a Memorandum of Understanding (MoU) inked in October 2024, reflecting a shared vision to enhance industrial growth.

The partnership leverages JSW's strong domestic presence and execution expertise with POSCO's advanced steelmaking technology. Odisha, with its rich natural resources and logistical advantages, is a frontrunner for the plant's location. A detailed feasibility study will determine the site, investment terms, and resource availability, with both companiesaiming to create a globally competitive manufacturing hub serving domestic and export markets. The initiative aligns with India's Atmanirbhar Bharat vision, promising job creation and economic upliftment.

JSW Steel's Joint Managing Director and CEO, Jayant Acharya, emphasized the synergy, stating the venture will strengthen India's steel ecosystem. POSCO Holdings' President, Lee Ju-tae, highlighted India's pivotal role in global steel demand, underscoring the partnership's commitment to sustainable growth and long-term value. With JSW's current capacity at 35.7 MTPA and POSCO's 42 MTPA global output, the alliance could reshape the industry landscape.

This move comes amid rising steel

demand in India, driven by infrastructure and automotive sectors. However, challenges like regulatory approvals and environmental concerns may influence the project's timeline. If successful, this collaboration could position India as a key player in the global steel market, blending technological innovation with local strengths.

Source: Business Standard

ऑरोबिंदो फार्मा $5.5 बिलियन की जेंटिवा खरीदने के करीब

भोपाल: ऑरोबिंदो फार्मा भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक के रूप में उभर रही है, जो प्राग स्थित जेनेरिक दवा निर्माता जेंटिवा को $5-5.5 बिलियन (लगभग 43,500-47,900 करोड़ रुपये) में खरीदने के करीब है। यह सौदा, जो एडवेंट इंटरनेशनल से होगा, भारतीय फार्मा उद्योग की अब तक की सबसे बड़ी अधिग्रहण सौदे के रूप में सामने आया है। यह डील 2014 में डाइची सांक्यो की रैनबैक्सी में $3.2 बिलियन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की $3.3 बिलियन की वियाट्रिस खरीद को पीछे छोड़ देगा।

हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि अभी तक कोई बाध्यकारी समझौता नहीं हुआ है। अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म जीटीसीआर भी इस सौदे में प्रतिस्पर्धी है। दोनों पक्ष वाणिज्यिक और परिचालन पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए गहन बातचीत में हैं। जेंटिवा, जिसकी 2024 में 1.7 बिलियन यूरो की आय रही, यूरोप में 30 देशों में संचालित है और 2028 तक वहां के पांच में से एक व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य रखती है।
यह अधिग्रहण ऑरोबिंदो की यूरोपीय उपस्थिति को मजबूत करेगा, खासकर पूर्वी यूरोप में। हालांकि, भू-राजनीतिक जोखिमों और शुल्क संभावनाओं के बीच इस साहसिक कदम ने विश्लेषकों को आश्चर्यचकित किया है। शेयर बाजार में कंपनी के शेयर बुधवार को 4.7% तक गिरे, लेकिन बाद में कुछ हद तक उबर गए।

Source: Mint

Marriott and Flipkart Unveil Integrated Loyalty Scheme

Bhopal: Marriott Bonvoy and Flipkart Super Coins have launched an innovative dual loyalty integration programme in India, marking a pioneering move in the travel and e-commerce sectors. Announced today, the partnership allows members to earn and exchange points between the two platforms, blending Marriott's global travel rewards with Flipkart's shopping ecosystem.

This collaboration enables millions of users to convert Flipkart Super Coins into Marriott Bonvoy points for hotel stays, upgrades, and travel experiences, or swap Bonvoy points for Super Coins to redeem on Flipkart purchases. With a 2:1 conversion ratio, members can link accounts to unlock benefits across 159 Marriott hotels in India and Flipkart's vast marketplace, including travel deals on Cleartrip and Flipkart Travel. The initiative, themed "Your Cart Takes You Places," aims to enhance everyday shopping with travel perks.

John Toomey, Marriott's Chief Commercial Officer for Asia Pacific (excluding China), highlighted the programme's potential to engage India's growing travel market, with plans to expand internationally soon. Manjari Singhal, Head of Flipkart Travel, emphasized enriching customer lifestyles through seamless rewards. With Marriott targeting 80 cities by 2026 and Flipkart reaching over 500 million users, the alliance taps into a combined base of 700 million members.This move strengthens India's travel and retail landscape, offering unparalleled value. However, experts suggest monitoring conversion rates and redemption flexibility to ensure long-term success. The programme is live, promising a new era of integrated rewards for Indian consumers.

Source: Economic Times

उल्ट्राटेक सीमेंट बेचेगी इंडिया सीमेंट्स में 6.5% तक की हिस्सेदारी

भोपाल: उल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने बुधवार को घोषणा की कि वह अपनी सहायक कंपनी इंडिया सीमेंट्स में 6.5% तक की हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। यह बिक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के जरिए की जाएगी। कंपनी ने कहा कि इस सौदे के तहत 2.01 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे, जो इंडिया सीमेंट्स की जारी और चुकता पूंजी का 6.49% है।

जुलाई 2024 में इंडिया सीमेंट्स पर नियंत्रण हासिल करने वाली उल्ट्राटेक की वर्तमान हिस्सेदारी 81.49% है। इस बिक्री के बाद उसकी हिस्सेदारी 75% तक कम हो जाएगी, जो सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों (25%) के अनुपालन के लिए आवश्यक है। सौदे का मूल्यांकन लगभग 744 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित है।

इं विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उल्ट्राटेक की रणनीतिक पुनर्संरचना का हिस्सा हो सकता है। पिछले साल अधिग्रहण के बाद इंडिया सीमेंट्स ने वित्तीय सुधार दिखाया है, लेकिन इस बिक्री से कंपनी के भविष्य पर नजर रखी जा रही है।

यह कदम भारत के सीमेंट उद्योग में उभरती प्रतिस्पर्धा और विलय-विक्रय की रणनीति को दर्शाता है, जहां बड़ी कंपनियां बाजार हिस्सेदारी मजबूत करने के लिए कदम उठा रही हैं।

Source: Business Standard

रिलायंस ने हर्बल ड्रिंक मार्केट में एंट्री, नेचरएज बेवरेजेस में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदी

भोपाल: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की एफएमसीजी शाखा, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने हेल्दी फंक्शनल बेवरेज सेगमेंट में प्रवेश किया है। कंपनी ने नेचरएज बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर एक संयुक्त उद्यम (जेवी) की स्थापना की है, जो हर्बल-नेचुरल ड्रिंक्स की नई रेंज पेश करेगा। यह कदम तेजी से बढ़ते स्वास्थ्य-केंद्रित पेय बाजार में रिलायंस की बढ़ती महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जहां उपभोक्ता स्वस्थ और प्राकृतिक विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं।

नेचरएज बेवरेजेस, जिसकी स्थापना 2018 में सिद्धेश शर्मा ने की थी, बैद्यनाथ ग्रुप के तीसरी पीढ़ी के उद्यमी हैं, जो आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। कंपनी का प्रमुख उत्पाद 'शुन्य ' एक जीरो-शुगर, जीरो-कैलोरी हर्बल ड्रिंक है, जिसमें अश्वगंधा, ब्राह्मी, खस, कोकम और ग्रीन टी जैसे भारतीय जड़ी-बूटियों का मिश्रण है। इस ड्रिंक ने health-conscious उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है। RCPL के कार्यकारी निदेशक केतन मोदी ने कहा, "यह जेवी हमारे पेय पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा और आयुर्वेद से प्रेरित स्वास्थ्य-केंद्रित ड्रिंक्स पेश करेगा, जो हमारे ग्राहकों के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के विजन से मेल खाता है।"

इस साझेदारी के तहत, रिलायंस अपनी विस्तृत वितरण नेटवर्क के

माध्यम से शुन्य को पूरे भारत में उपलब्ध कराएगी। सिद्धेश शर्मा, नेचरएज बेवरेजेस के निदेशक, ने कहा, "RCPL के साथ यह साझेदारी शुन्य की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। हमारा लक्ष्य इसे एक पैन-इंडिया ब्रांड बनाना है, जो उपभोक्ताओं को ताजगी और स्वाद प्रदान करे।" यह कदम रिलायंस के लिए एक रणनीतिक विस्तार है, क्योंकि कंपनी पहले से ही कैंपा, सोसियो और रसकिक जैसे ब्रांड्स के साथ पेय बाजार में मजबूत स्थिति बना चुकी है।

हेल्दी ड्रिंक्स का बाजार भारत में तेजी से बढ़ रहा है, और इस सेगमेंट में रिलायंस की एंट्री प्रतिस्पर्धा को और गहरा कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग बढ़ने के साथ, यह कदम रिलायंस को लंबी अवधि में लाभ पहुंचा सकता है। भविष्य में, कंपनी और नवाचार के साथ नई ड्रिंक रेंज लाने की योजना बना रही है, जो उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को पूरा करेगी।

Source: Business Standard

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

AII level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	24870	25361	25256	25063	24958	24765	24660	24467
BANK NIFTY	55149	56880	56518	55833	55471	54786	54424	53739
SENSEX	81307	82976	82600	81954	81578	80932	80556	79910
FINNIFTY	26317	27211	27025	26671	26485	26131	25945	25591
MIDCAP	12936	13391	13224	13080	12913	12769	12602	12458
ACC	1822	1919	1897	1859	1837	1799	1777	1739
AXISBANK	1071	1112	1104	1087	1079	1062	1054	1037
ABCAPITAL	286	311	301	294	284	277	267	260
BHARTIARTL	1934	2046	1999	1966	1919	1886	1839	1806
BHEL	218	234	230	224	220	214	210	204
BIOCON	359	378	372	366	360	354	348	342
CDSL	1575	1659	1636	1605	1582	1551	1528	1497
DATAPATTERN	2600	2847	2760	2680	2593	2513	2426	2346
ESCORTS	3574	3969	3845	3709	3585	3449	3325	3189
EICHERMOTOR	5944	6232	6128	6036	5932	5840	5736	5644
FEDERAL BANK	197	206	204	200	198	194	192	188
GRINFRAPOJECT	1279	1321	1304	1292	1275	1263	1246	1234
HDFCBANK	1966	2078	2052	2009	1983	1940	1914	1871
HCLTECH	1467	1542	1524	1495	1477	1448	1430	1401
HINDUNILVR	2632	2834	2757	2694	2617	2554	2477	2414
HAL	4480	4751	4675	4578	4502	4405	4329	4232
HYUNDAI	2365	2882	2753	2559	2430	2236	2107	1913
IOC	140	146	145	142	141	138	137	134
ICICIBANK	1436	1479	1465	1451	1437	1423	1409	1395
INFY	1488	1599	1553	1521	1475	1443	1397	1365
ITC	398	424	419	408	403	392	387	376
KOTAKBNK	1984	2081	2060	2022	2001	1963	1942	1904
LICHOUSING	564	600	592	578	570	556	548	534
LT	3593	3787	3743	3668	3624	3549	3505	3430
LUPIN	1971	2048	2017	1994	1963	1940	1909	1886
MARUTI	14370	15350	14875	14623	14148	13896	13421	13169
M&M	3400	3534	3483	3441	3390	3348	3297	3255
MGL	1326	1399	1375	1351	1327	1303	1279	1255
MAZGAONDOC	2700	2939	2889	2795	2745	2651	2601	2507
PFC	399	441	430	415	404	389	378	363
RECLTD	376	396	391	384	379	372	367	360
RELIANCE	1410	1491	1461	1436	1406	1381	1351	1326
SBIN	817	850	843	830	823	810	803	790
SUNPHARMA	1640	1692	1672	1656	1636	1620	1600	1584
SHRIRAMFINANCE	616	655	646	631	622	607	598	583
TITAN	3619	3820	3730	3675	3585	3530	3440	3385
TCS	3055	3249	3190	3122	3063	2995	2936	2868
TATAMOTORS	681	728	716	698	686	668	656	638
UPL	714	777	753	734	710	691	667	648
VALIENT	350	412	397	374	359	336	321	298
WIPRO	249	261	257	253	249	245	241	237

एलएंडटी और जापान की आईटीओसीएचयू ने गुजरात में ग्रीन अमोनिया परियोजना के लिए साझेदारी की

भोपाल: लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एलएंडटी एनर्जी ग्रीनटेक लिमिटेड (एलटीईजी) ने जापान की आईटीओसीएचयू कॉर्पोरेशन के साथ गुजरात के कांडला में 300 किलो टन प्रति वर्ष (केटीपीए) क्षमता की ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी समुद्री क्षेत्र के लिए शून्य-उत्सर्जन ईंधन समाधान प्रदान करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए की गई है।

इस समझौते के तहत, एलटीईजी और आईटीओसीएचयू ग्रीन अमोनिया संयंत्र के विकास में सहयोग करेंगे, जिसमें आईटीओसीएचयू इस उत्पाद को सिंगापुर में बंकरिंग अनुप्रयोगों के लिए लेगी। कांडला, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित, इस परियोजना का प्रमुख उत्पादन केंद्र बनेगा। यह कदम दोनों कंपनियों की कार्बन उत्सर्जन में कमी और सतत ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एलएंडटी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सुब्रमण्यम सरमा ने कहा, "यह साझेदारी एलएंडटी के साफ और हरे भविष्य के विजन को मजबूत करती है।" इसी तरह, आईटीओसीएचयू के हिरोयुकी त्सुबाई ने कहा, "यह सहयोग समुद्री क्षेत्र में कम-कार्बन अमोनिया को बढ़ावा देगा।" यह परियोजना पिछले साल कांडला में अधिग्रहित भूमि पर आधारित है, जो ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं के लिए तैयार की गई थी।

यह पहल भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है, जो 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन लक्ष्य रखता है। यह साझेदारी भारत को ग्रीन ऊर्जा के वैश्विक बाजार में अग्रणी बना सकती है।

Source: The Financial Expres

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in